

असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद का समाधान

प्रलिस के लयि:

[सर्वे ऑफ इंडिया](#), [बेलागवी](#), [राज्य पुनरगठन अधनियिम, 1956](#), [महाजन आयोग](#), [लुशाई हलिस](#), [खासी और जयंतया हलिस](#), [भारतीय संवधान का अनुच्छेद 131](#)

मेन्स के लयि:

भारत में राज्यों के बीच सीमा विवाद, [अंतरराज्यीय परषिद](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [असम और अरुणाचल प्रदेश](#) के बीच वर्ष 1972 से चले आ रहे सीमा विवाद का स्थायी समाधान हो गया है।

- असम और अरुणाचल प्रदेश 804 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं।

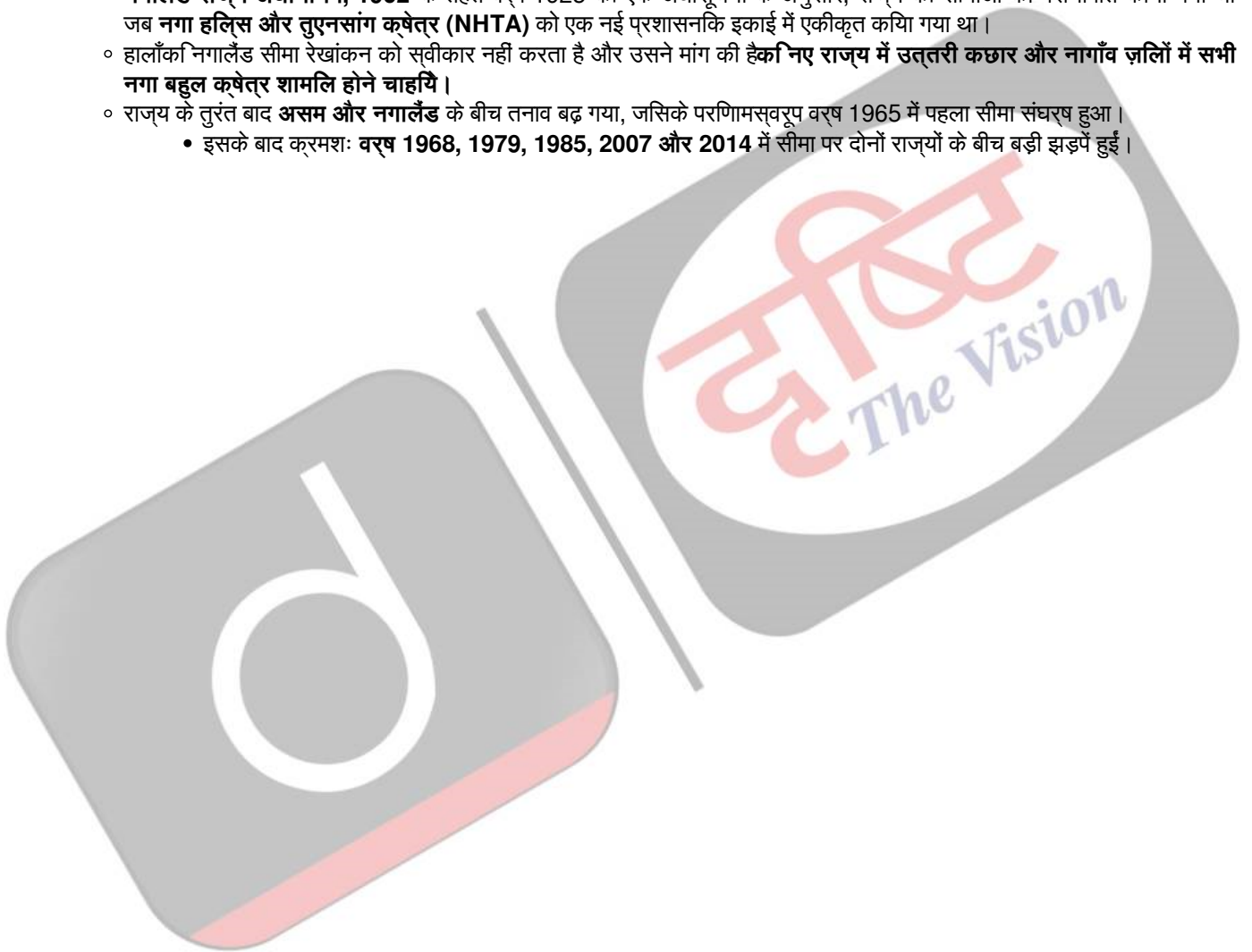
समझौते के प्रमुख बडि:

- इस समझौते से ऐतहासकि परपिरेक्ष्य, जनसांख्यकीय प्रोफाइल, प्रशासनकि सुवधा, सीमा की नकिटता और नवासिथिों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्यों के बीच 700 किलोमीटर से अधिक की सीमा को कवर करने वाले 123 गाँवों से संबंधति विवाद का समाधान होने की उम्मीद है।
 - यह अंतमि समझौता होगा जिसके अंतरगत कोई भी राज्य भवषिय में किसी भी क्षेत्र या गाँव से संबंधति कोई नया दावा नहीं करेगा
- समझौते के बाद सीमाओं का नरिधारण करने के लयि दोनों राज्य सरकारों के प्रतनिधियों की उपस्थति में [सर्वे ऑफ इंडिया](#) द्वारा एक वसितृत सर्वेक्षण कया जाएगा।

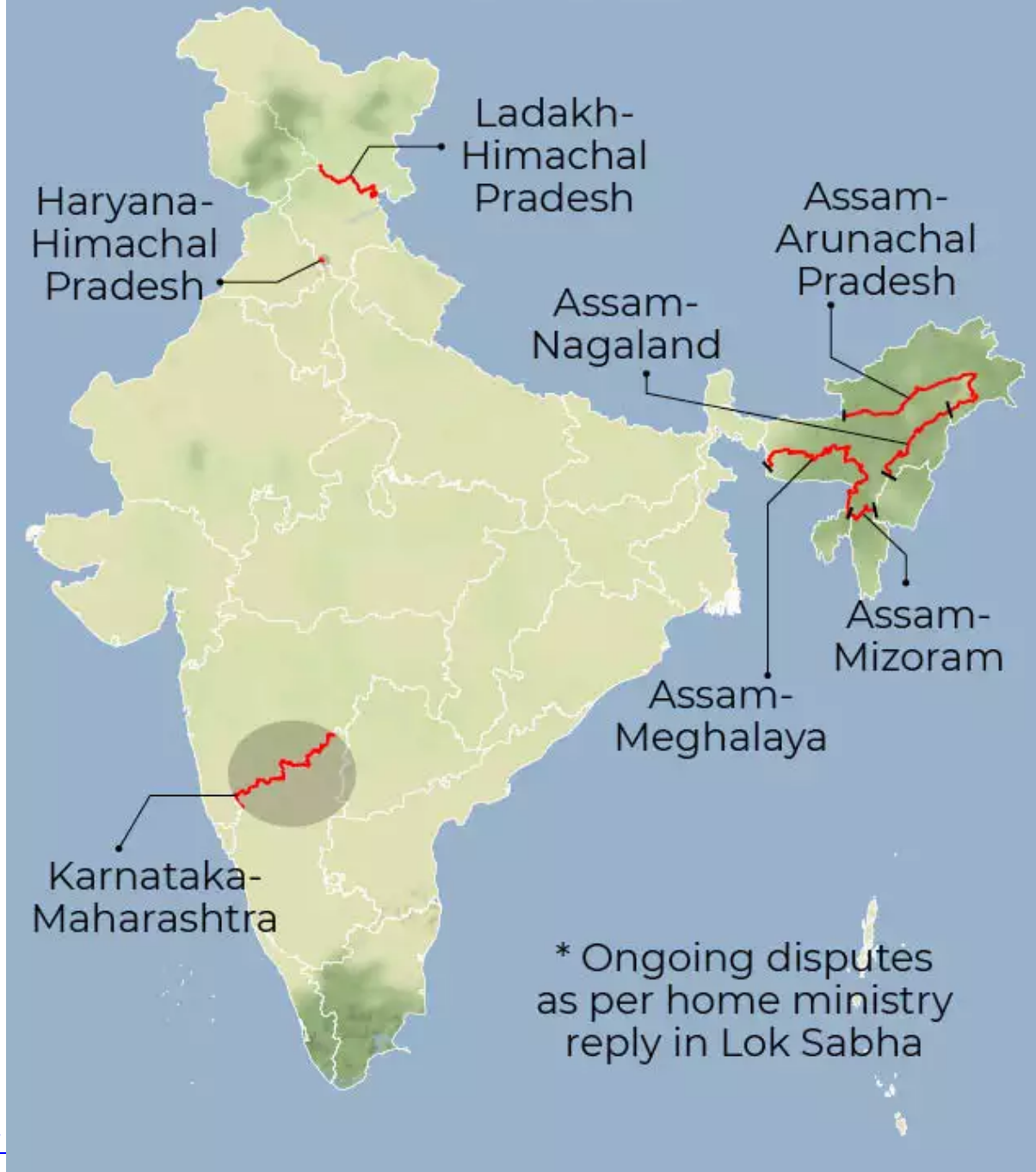
भारत में राज्यों के बीच अन्य सीमा विवाद:

- कर्नाटक-महाराष्ट्र:
 - उत्तरी कर्नाटक में [बेलगावी](#), कारवार और नपिनी को लेकर सीमा विवाद काफी पुराना है। 1956 के राज्य पुनरगठन अधनियिम के अनुसार, जब राज्य की सीमाओं को भाषायी आधार पर पुनः तैयार कया गया, तो बेलगावी पूर्ववर्ती मैसूर राज्य का हसिसा बन गया।
 - यह अधनियिम न्यायमूर्तफिजल अली आयोग के नषिकर्षों पर आधारति था जसि 1953 में नयिकृत कया गया था और इसने दो वर्ष बाद अपनी रपिर्ट प्रसतुत की।
 - महाराष्ट्र का दावा है कि बेलगावी के कुछ हसिसे, जहाँ मराठी प्रमुख भाषा है, को महाराष्ट्र में ही रहना चाहयि।
 - अक्टूबर 1966 में केंद्र ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में सीमा विवाद को हल करने के लयि [महाजन आयोग](#) की स्थापना की।
 - आयोग ने सफिरशि की कि बेलगाम और 247 गाँव कर्नाटक में ही रहेंगे। महाराष्ट्र ने रपिर्ट को खारजि कर दया और वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय का रुख कया
- असम-मजिोरम:
 - असम और मजिोरम के बीच सीमा विवाद वर्ष 1875 और वर्ष 1933 की ब्रिटिश काल की दो अधसिचनाओं की वरिसत है, जब मजिोरम को असम का एक ज़िला [लुशाई हलिस](#) कहा जाता था।
 - वर्ष 1875 की अधसिचना ने लुशाई हलिस को कछार के मैदानों से तथा लुशाई हलिस और मणपुरि के बीच अन्य सीमांकति सीमा से अलग कर दया।
 - जबकि मजिोरम वदिरोह के वर्षों के बाद वर्ष 1987 में ही एक राज्य बन गया था, यह अभी भी वर्ष 1875 में तय की गई सीमा पर ज़ोर देता है।
 - दूसरी ओर असम वर्ष 1986 में (1933 की अधसिचना के आधार पर) सीमा का सीमांकन चाहता था

- **हरियाणा-हमिचल प्रदेश:**
 - दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर **परवाणू क़्षेत्र** सुरक्षियों में रहा है ।
 - यह **हरियाणा के पंचकुला ज़िले** के नकिट है और हरियाणा ने **हमिचल प्रदेश** में भूमि के कुछ हसिसों पर अपना दावा जताया है ।
- **हमिचल प्रदेश-लददाख:**
 - हमिचल और लददाख **लेह तथा मनाली** के बीच के मार्ग के एक क़्षेत्र **सरचू** पर दावा करते हैं ।
 - यह एक प्रमुख बडुि है जहाँ यात्रीगण इन दो शहरों के बीच यात्रा के दौरान रुकते हैं ।
 - **सरचू** हमिचल के **लाहुल तथा स्पीता ज़िले** और **लददाख के लेह ज़िले** के बीच में है ।
- **मेघालय-असम:**
 - **असम और मेघालय के बीच सीमा को लेकर समस्या तब शुरू हुई** जब मेघालय ने **पुरवोत्तर क़्षेत्र (पुनरगठन) अधिनियम, 1971** को चुनौती दी जिसके तहत **मकिरि हलिस अथवा वर्तमान के कारबी आंगलॉग ज़िले के खंड I और II असम को सौंप दिये गए थे** ।
 - मेघालय का तर्क है कि जब वर्ष 1835 में दोनों खंडों को अधिसूचित किया गया था, तब ये दोनों खंड तत्कालीनसंयुक्त **खासी और जयंतिया हलिस ज़िले** का हसिसा थे ।
- **असम-नगालैंड:**
 - वर्ष **1963** में **नगालैंड राज्य के रूप में स्थापति होने** के तुरंत बाद सीमा संबंधी विवाद की शुरुआत हो गई ।
 - **नगालैंड राज्य अधिनियम, 1962** के तहत वर्ष 1925 की एक अधिसूचना के अनुसार, राज्य की सीमाओं को परिभाषित किया गया था जब **नगा हलिस और तुएनसांग क़्षेत्र (NHTA)** को एक नई प्रशासनिक इकाई में एकीकृत किया गया था ।
 - हालाँकि नगालैंड सीमा रेखांकन को स्वीकार नहीं करता है और उसने मांग की है कि **राज्य में उत्तरी कछार और नागाँव ज़िलों में सभी नगा बहुल क़्षेत्र शामिल होने चाहिये** ।
 - राज्य के तुरंत बाद **असम और नगालैंड** के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1965 में पहला सीमा संघर्ष हुआ ।
 - इसके बाद क्रमशः **वर्ष 1968, 1979, 1985, 2007 और 2014** में सीमा पर दोनों राज्यों के बीच बड़ी झड़पें हुईं ।



Border wars



भारत में सीमा विवादों के समाधान के अन्य तरीके:

■ अनुसूचित जातिके विशेष मूल अधिकार क्षेत्र के माध्यम से:

- **भारत के संविधान के अनुच्छेद 131** के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के पास अनन्य मूल क्षेत्राधिकार है, जिसका अर्थ है कि कोई अन्य न्यायालय इन मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है:
 - यह भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों को सुनवाई कर सकता है।
 - यह एक तरफ भारत सरकार और किसी भी राज्य (राज्यों) और दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई कर सकता है।
 - यह दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों को सुनवाई कर सकता है यदि विवाद में कानून या तथ्य का प्रश्न शामिल है जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या सीमा निर्भर करती है।
- **क्षेत्राधिकार से संबंधित सीमाएँ:** सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन संधियों, समझौतों, प्रसंविदाओं, अनुबंधों या इसी तरह के

अन्य आयामों से उत्पन्न होने वाले ऐसे विवादों तक नहीं है जो संविधान के प्रारंभ से पहले दर्ज किये गए थे या इनके द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है कि इसका क्षेत्राधिकार ऐसे विवादों तक विस्तारित नहीं होगा।

■ अंतरराज्यीय परिषद द्वारा:

- संविधान का अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है।
- यह राज्यों के बीच चर्चा और विवादों के समाधान के साथ-साथ राज्यों या संघ एवं एक या अधिक राज्यों के बीच सामान्य हितों से संबंधित विषयों पर चर्चा हेतु एक मंच के रूप में कार्य करती है।
- वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी।
 - वर्ष 2021 में इस परिषद का पुनर्गठन किया गया था।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. अंतरराज्यीय जल विवादों को हल करने हेतु उपलब्ध संविधानिक तंत्र संबंधित समस्याओं को हल करने में विफल रहा है। क्या यह विफलता संरचनात्मक या प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता या दोनों कारणों से है? चर्चा कीजिये। (2013)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/settlement-of-border-dispute-between-assam-and-arunachal-pradesh>

